आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 03.01.2026
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 88 करोड रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की।
- मुख्य सचिव ने कार्बन क्रेडिट को आय का स्रोत बनाने के लिए विभागों को सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिये।
- प्रदेश में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम खोजने की प्रक्रिया हुई आसान। अब क्षेत्र या गली–मोहल्ले के नाम से भी मिलेगी प्रविष्टि।
- जन– जन की सरकार जन–जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश भर में जारी। 12 हजार से अधिक लोगों की समस्याओं का किया गया समाधान।

धनराशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 88 करोड 84 लाख की धनराशि का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के शारदा घाट परियोजना के अन्तर्गत सिटी ड्रेनेज प्लान फेज–1 के निर्माण के लिए ₹65 करोड़ 65 लाख रूपये की स्वीकृत दी। मुख्यमंत्री ने देहरादून के जैलीग्रान्ट एयरपोर्ट में स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 4 करोड 46 लाख की धनराशि स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले के समग्र जल संरक्षण–जल संवर्धन व मृदा संरक्षण पुनरोद्धार से संबंधित कार्य के लिए तीन करोड 39 लाख की योजना जलागम प्रबन्धन के अन्तर्गत स्वीकृत की। साथ ही जिला कार्यालय, देहरादून के लिए 3 बोलेरो वाहन खरीदने की अनुमति दी है।

दो नई बसें

शासन ने चंपावत जिले के लोहाघाट डिपो को दो नई बसें उपलब्ध कराई है, इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। दोनों नई बसों का संचालन देहरादून रूट पर किया जा रहा है। डिपो के सहायक महाप्रबंधक धीरज वर्मा ने बताया कि यह नई बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। उन्होंने कहा कि अभी और बसों की जरूरत है, इसलिए शासन से 15 और नई बसों की मांग की गई है। लोहाघाट डिपो में बसों की कमी के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दो नई बसें मिलने से यात्रियों को आंशिक राहत मिलेगी।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने

अल्मोड़ा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में हादसों की समीक्षा की गई और संवेदनशील स्थलों पर सुधारात्मक कार्रवाई पर जोर दिया। इस मौके पर श्री टम्टा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए रोड़ के डिजाइन और आवश्यक कार्यों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री टम्टा ने कहा कि सड़क सुरक्षा में जनता की सहभागिता भी जरूरी है। इस दिशा में जागरूकता अभियान, स्कूल और कॉलेज में कार्यशालाएं और रैलियों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि नेक राहवीर योजना के तहत अब घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

श्रीनंदा देवी राजजात यात्रा

वर्ष 2026 में होने वाले श्रीनंदा देवी राजजात की यात्रा कार्यक्रम के लिए नौटी में तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा के आयोजन को लेकर बसंत पंचमी को कार्यक्रम जारी होगा। श्रीनंदा देवी राजजात समिति के महासचिव भुवन नौटियाल ने बताया कि 20 दिनों तक चलने वाले श्रीनंदा देवी राजजात यात्रा का कार्यक्रम बसंत पंचमी 23 जनवरी को राजवंशी राजकुंवर जारी करेंगे। इसके लिए नौटी में 20 जनवरी से महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें देवी पूजन के अलावा अन्य कार्यक्रम जारी होंगे।

कार्बन क्रेडिट

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में कार्बन क्रेडिट को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए कार्बन क्रेडिट एक महत्त्वपूर्ण आय का श्रोत बन सकता है। इसके लिए विभागों को अपने–अपने कार्यक्षेत्र में सम्भावनाएं तलाशनी होंगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए कार्बन क्रेडिट भविष्य में एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन सकता है। इसके लिए सभी विभागों को अपने–अपने क्षेत्रों में संभावनाओं की पहचान करनी होगी और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की दिशा में आवश्यक तैयारियां करनी होंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यावरण विभाग, कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और शुरुआत में ऐसे क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, जहां अपेक्षाकृत जल्दी सफलता मिल सकती है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही हैं, जिससे परिवहन विभाग को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा वन पंचायतों के जरिए वन विभाग और पैक्स के माध्यम से सहकारिता विभाग भी कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।

गौरतलब है कि कार्बन क्रेडिट एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें जो लोग या कंपनियाँ कम प्रदूषण करती हैं उन्हें फायदा मिलता है, और जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं उन्हें उसकी भरपाई करनी पड़ती है, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे।

एस आई आर

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) के लिए उत्तराखंड के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम खोजना आसान हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाताओं की सुविधा के लिए नया यूजर इंटरफेस तैयार किया है। अब मतदाता केवल अपने गली, मोहल्ले एवं एरिया के नाम के आधार पर भी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकेंगे। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि प्रदेश के कई मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अपने वर्ष 2003 के बूथों की सही जानकारी नहीं हैं। मतदाताओं की इस परेशानी को देखते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर 2003 की मतदाता सूची को और सरल विकल्प के साथ सर्च करने की सुविधा प्रदान की गई। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में आगामी 10 जनवरी तक बीएलओ आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बीएलओ घर–घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर उनकी 2003 की मतदाता सूची में जानकारी से मिलान कर रहे हैं।

जनसंपर्क अभियान

"जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार" कार्यक्रम प्रदेशभर में जारी है। इस जनसंपर्क अभियान के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में कल एक ही दिन में 204 जनसेवा कैम्प लगाए गए, जिनमें 1 लाख 35 हजार से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की।

इन कैम्पों के माध्यम से शासन–प्रशासन सीधे जनता के द्वार पहुँच रहा है, जिससे ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला या तहसील मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ रहा है। इस पहल से तहत अब तक 17 हजार 747 शिकायतें और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12 हजार 776 मामलों का मौके पर अथवा त्वरित कार्रवाई के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर समयबद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

शिविरों में आय, जाति, निवास और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों से संबंधित 19 हजार 734 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 77 हजार 203 नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ दिया गया है। एक ही मंच पर सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलने से आम लोगों को सुविधा मिल रही है।